

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. सचिव,
श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 19 अगस्त, 2016

विषय :- राज्याधीन सेवाओं में नियुक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने हेतु कार्मिकों के वेतनमान एवं अन्य भत्तों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग-7 से जारी पत्र संख्या 145/XXVII(7)50(16)/2016, दिनांक 27 जून, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त वर्णित पत्र द्वारा शासन के प्रशासनिक विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को विषयगत सूचनायें कोषागार साफ्टवेयर के माध्यम से वेतन समिति को प्रत्येक दशा में दिनांक 15 जुलाई, 2016 से पूर्व आन लाइन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

वेतन समिति ने अपने पत्र संख्या 14/वेतन समिति/2/2016, दिनांक 19-08-2016 द्वारा अवगत कराया है कि केन्द्रीय सातवें वेतन आयोग की संस्तुति पर राज्य सरकार के कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षित किये जाने के संदर्भ में विषयगत वॉछित महत्वपूर्ण सूचनाएँ अभी तक किसी भी विभागाध्यक्ष द्वारा समिति को उपलब्ध नहीं कराया गयीं हैं।

अतः उक्त के कम में अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को अनुश्रवण कराते हुए निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे समयबद्ध रूप से प्राथमिकता के आधार पर उक्त सूचनाएँ साफ्टवेयर के माध्यम प्रत्येक दशा में 05-09-2016 से पूर्व वेतन समिति को आन लाइन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 183 / XXVII(7)50(16)/2016,,

प्रतिलिपि: :-

1. मुख्य स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, वेतन समिति, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त कुमायू/गढ़वाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषागार/उपकोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने कोषागार/उपकोषागार अधिकारी से सम्बद्ध आहरण वितरण अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके वांछित सूचनाओं को वेतन समिति को आन लाइन उपलब्ध कराने के व्यवस्था अपने स्तर से भी सुनिश्चित करें।

(अरुणेंद्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।